संबंधित कार्यकलापों के विकास के लिए आवंटित की गयी राशि इस प्रकार है :–

कृषि और संबंधित कार्यकलापों (वानिकी और वन्यजीवन सहित) के अन्तर्गत स्वीकृत उपरिव्यय

(करोड़ रुपये में)

	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	योग
1991–92	1857.85	2565.21	50.04	4473.10
1992–93	1879.27	2784.83	46.18	4710.28
1993–94	2435.83	2921.54	51.56	5408.93

कुल (योजनागत आबंटन की तुलना में इन आबंटनों का प्रतिशत 6.18 (1991-92), 5.83 (1992–93) और 5.40 (1993–94) था ।

"पेप्सी डिसिरगार्डस फार्मर्स क्लेम्स"

7153. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अप्रैल, 1994 के "स्टेट्समैन" में "पेप्सी डिस्रिगार्डस फार्मस क्लेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस बहुराष्ट्रिक कम्पनी ने पंजाब में किसानों को झूठा आश्वासन देकर उन्हें भारी आर्थिक संकट में डाल दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार भविष्य में किसानों के संरक्षण हेतु बहुराष्ट्रीक कम्पनियों अथवा अन्य ऐसे तत्वों का कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Criteria for fixing of support prices

7154. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: ..

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the criteria, for fixing up support prices for agricultural commodities like wheat, rice, sugar, pulses, edible oils etc;

(b) whether support price criteria takes into consideration various agro-climatic zones, if so, in what manner;

(c) whether support prices are interpretable as subsidies or they are the actual cost prices or the remunerative prices; and

(d) what is the relationship of international prices of the agricultural commodities with our local support prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The Government decide on support prices for various agricultural commodities after taking into account the recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), views of State Governments and Central Ministries as well as such other